स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–19, अंक–9, भाद्रपद–आश्विन 2068, सितम्बर 2011

संपादक
विक्रम उपाध्याय

कार्यालय
धर्मक्षेत्रा, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी
दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

आवरण कथा-4

भारत के सुरक्षा अधिकारियों ने देश के सामने अपनी मजबूरी जताते हुए कहा कि उन्हें आतंकवादी हमलों के बारे में खुफिया जानकारी होने के बावजूद हमले रोकने में कामयाबी नहीं मिली।

अनुक्रम

आवरण लेख
चुनौतियों के आगे ढ़ेर नेतृत्व
– विक्रम उपाध्याय /4

सामयिकी
नए संघर्ष की शुरूआत
– बलवीर पुंज /7

जन आंदोलन
देश की जनता जाग चुकी है
– निरंकार सिंह /10

अंतर्राष्ट्रीय
चीन का राजनीतिक हथियार
– ब्रह्मा चेलानी /13

बाढ़
बाढ़ ग्रस्त ग्रामीण इलाकों की पीड़ा
– भारत डोगरा /15

दृष्टिकोण
मुंबई की बाढ़ को रोकने का सिंगापुरी तरीका
– डॉ. अश्विनी महाजन /18

अर्थव्यवस्था
वैश्विक कर्ज संकट से मुश्किलें
– डॉ. जयंती भंडारी /20

विचार–विमर्श
पुराने उपायों से संभव नहीं समाधान
– आलोक पुराणिक /23

मुद्दा
क्यों नहीं सफल है एयर इंडिया...?
– डॉ. भरत झुनझुनवाला /25

लेख
भारतीय परिवार
– रेणु पुराणिक /27

स्वास्थ्य चिंतन
पर्यावरण एवं स्वास्थ्य – आयुर्वेदीय दृष्टिकोण
– डॉ. योगेश चन्द मिश्र /29

पाठकनामा/2, रपट/33, आंदोलन/35

पाठकनामा

शिक्षा बनाम वाइन कल्चर

मुझे स्वदेशी पत्रिका से काफी कुछ सीखने को मिला है और पत्रिका को पढ़कर देश की समस्याओं के बारे में पता चलता है। आज हमें आजादी प्राप्त हुए 64 वर्ष पूरे हो चुके हैं लेकिन शिक्षा के विषय में हम विकसित देशों के मुकाबले काफी पीछे है। सरकार ने जनता को लुभाने के लिए आठवीं तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, इसका नियम बना दिया है परंतु सरकारी स्कूलों का क्या हाल है यह किसी से छिपा नहीं है। आज भी सरकारी शिक्षक हो या नगर निगम का कर्मचारी या फिर सिपाही सभी अपनी नौकरी को ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। हां एक विकास जरूर हो रहा है और वह है मदिरा की बिक्री। आज देश की राजधानी दिल्ली के वासियों पर वाइन कल्चर दिन प्रति दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसका अंदाजा आबकारी विभाग की वाइन की बिक्री से हो रही मोटी कमाई से लगाया जा सकता है। एक्साइज डिपार्टमेंट के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष वाइन की बिक्री में 60 फीसदी से भी अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब महिलाएं भी शराब पीने में दिलचस्पी ले रही हैं क्योंकि नामी गिरमी शराब कंपनियां अपने वाइन के विज्ञापन पर लुभावने वाला प्रचार करती है जिसके कारण युवा वर्ग वाइन कल्चर को अपनाने लगा है। क्या हो गया है सरकार को, जहां सरकार का फर्ज बनता था कि युवा वर्ग को ठीक शिक्षा की व्यवस्था की जाए। वही दूसरी ओर सरकार अपनी कमाई के आंकड़ों को प्रस्तुत करती रहती है। सरकार को अपनी गलती सुधारी चाहिए अन्यथा आने वाला युवा वर्ग कही शिक्षा में विकास न करके वाइन कल्चर में विकास न कर जाए।

– विनोद कुलियाल, सेक्टर–3, आर.के. पुरम्, नई दिल्ली

लापरवाह अधिकारियों और लापरवाह नेताओं को मिलें दण्ड

एक बार फिर देश आतंकवाद की चपेट में आ गया। दिल्ली में हाई कोर्ट के बाहर हुए विस्फोट से देश की जनता बार–बार, देश के नेताओं से और सुरक्षा अधिकरियों से गुहार लगती है कि आखिर कब तक हम इन हादसों के शिकार होते रहेंगे। हाई कोर्ट में सीसी टीवी कैमरे या फिर खराब मेटल डिटेक्टर, कुल मिलाकर यह स्पष्ट हो गया कि आधे अधूरे सुरक्षा इंतजामों के चलते ही यह घटना घटी। पुलिस प्रशासन अपनी कमी को न बताकर गेंद एक–दूसरे के पाले में डालने को लगे हुए हैं। होना यह चाहिए था कि हाई कार्ट में सुरक्षा की जिम्मेदारी किस को दी गई थी, उन सबको तुरंत निलंबित कर देना चाहिए था। क्योंकि हर बार सुरक्षा की लापरवाही से यह घटना होती रहती है। हाई कोर्ट में मारे गए परिवार वाले भी मंत्रियों और सुरक्षा अधिकारियों से यही गुहार लगा रहे थे कि आखिर कब तक हम इन आतंकवादियों की गतिविधियों का शिकार होंगे – परंतु सरकार खामोश बैठी है।

– श्याम सलोना, युवा पत्रकार, पटेल चेस्ट (दिल्ली यूनिवर्सिटी)

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

"धर्मक्षेत्र" शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 100 रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्क: 1,000 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

(ध्यानार्थ : कृपया अपना नाम व पता साफ अक्षरों में लिखें)

उन्होंने कहा

'नोट के बदले वोट' ऐसे कार्यों में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी सांसद या विधायक को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए।"

– अन्ना हजारे

नेताओं पर टिप्पणी करने से अगर कुछ बदलाव हुआ, तो यह करने में कुछ गलत नहीं था। वह जनता की आवाज थी। किसी को दुखी करने का मेरा मकसद नहीं था और मैं संसद का सम्मान करती हूं।

– किरन बेदी

मैंने कुछ भी गलत या गैरकानूनी काम नहीं किया है। मैंने अपने दो दशक लंबे सार्वजनिक जीवन में उठे सभी सवालों के जवाब पूरी प्रामाणिकता के साथ दिए हैं।

– रामदेव बाबा

संपादकीय

जनता को जेब में रखने वाले सावधान!

लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, यह तथ्य विगत कुछ वर्षों में किताबों में या भाषणों में दब कर रह गया था। अन्ना के आंदोलन में इसे फिर से लोकतंत्र के चेहरे पर चमक के रूप में फिर से स्थापित कर दिया है। संसद हो या विधानसभा, सासंद या विधायक। यह कहने की हिम्मत अब नहीं कर सकते कि वे चुने हुए प्रतिनिधि के नाते जो उचित समझेंगे, कहेंगे या करेंगे। अन्ना के आंदोलन में जनता को जेब में रखने वाले नेताओं को भरपूर आईना दिखा दिया है। जिस प्रधानमंत्री ने आंदोलन से पहले यह कहकर सबको चौंका दिया था कि सामाजिक क्षेत्र के स्थापित लोगों की जिद लोकतंत्र के लिये खतरा है। उसी प्रधानमंत्री ने बड़े ही दयनीय भाव से यह स्वीकार किया कि सामाजिक प्रतिष्ठा वाले लोग ही दरअसल लोकतंत्र के गहने हैं। सबक सिखाने से लेकर खुद सबक सीखने की प्रक्रिया में लोकतंत्र ने कई बार हिचकोले खाये। एक बार को ऐसा लगा कि जनता और सरकार के बीच जबरदस्त टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है और इस टकराव के कारण शायद 1975 की तरह देश शायद एक बार फिर आपातकाल की स्थिति में पहुंच जाये। सही मौके पर जनता के प्रतिनिधि होने की दुहाई देने वाले होश में आये और उन्होंने जनता के दवाब को समझा जाना और जनता के समर्थन में कानून बनाने की गंभीर कोशिश का आश्वासन दिया। अन्ना के आंदोलन का यह एक गुणकारी प्रभाव था। अन्ना के आंदोलन से एक बात और उभर कर सामने आयी और वह यह बात है कि आजादी के 65 साल बाद भी देश सचमुच लोकतंत्र की आस्था से जुड़ नहीं पाया है। कहने को जनता अपने मतों का अधिकार कर जनप्रतिनिधि चुनती है और जनप्रतिनिधि अपने विवेक का इस्तेमाल कर सरकार बनाते हैं और सरकारें अपने विवेक का इस्तेमाल कर कानून बनाती हैं। पर वास्तविकता लगातार दूर होती जा रही है। देश आजाद हुआ, केंद्र और राज्य में लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो गया, थोड़े दिन तक सरकारें जनता के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने की ईमानदार कोशिशें की लेकिन बाद के काल में जैसे–जैसे लोकतंत्र पर नेतातंत्र हावी हुआ, नेतातंत्र पर गुण्डातंत्र हावी हुआ और बाद में यही गुण्डातंत्र सफेद वस्त्र पहनकर अनैतिकता और भ्रष्टाचार के रूप में सामने आ खड़ा हुआ। वैसे–वैसे लोकतंत्र की आत्मा दुर्बल होती गयी और भारतीय गणतंत्र एक तरफ से गुणतंत्र बनकर रह गया। जहां कुछ लोग मिलकर देश को मनमाफिक तरीके से चलाने लगे, लूटपाट मचाने लगे और जनता को मालिक नहीं अपना नौकर समझने लगे। जाहिर है इस व्यवस्था में परिवर्तन अति अनिवार्य था और यह एक सामान्य तरीके से संभव नहीं था क्योंकि लोकतंत्र के पहरूये के रूप में जिन राजनीतिक दलों ने अपने आप को जनता के सामने पेश किया। उन सबमें लगभग समान दोष भर गये। ऐसा तंत्र हावी हुआ, भाई–भतीजावाद जोरों से चलने लगा और जनहित के बजाय स्वहित का पोषण मूलमंत्र बन गया। यह महसूस किया जाने लगा कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था शायद ही इन विकारों को दूर सकें इसीलिये किसी मसीहे की तलाश में भारतीय लोकतंत्र समाज की ओर टकटकी लगाये हुए था। कई सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन भी चले पर उनका अलग–अलग समय पर अलग–अलग प्रभाव रहा। पूरा देश एक सूत्र में पिरोने की क्षमता किसी सामाजिक आंदोलन में नहीं दिखी। लेकिन अन्ना के आंदोलन ने देश को एक नई करवट लेने पर मजबूर कर दिया। अन्ना सिर्फ प्रतीक थे, बदलाव के प्रतीक, जिजीविषा और अदम्य इच्छा लोगों के अन्दर कूट–कूट कर भरी थी। लोग वर्तमान व्यवस्था से पूरी तरह ऊब चुके थे। राजनैतिक पार्टियों की अर्कमण्यता और सरकार की निरंकुशता जनता को रोज–रोज मार रही थी इसीलिये अन्ना की चिंगारी ने इतना बड़ा मशाल जला दिया। आजादी के बाद देश फिर एक बार जगा। संसद और विधानसभा बौनी दिखाई देने लगी। लोगों की इच्छा और संकल्पशीलता भारी पड़ी। बदलाव की कहानी का प्राक्कथन लिखा जा चुका है। देखें इस पर किस तरह की इमारत खड़ी होती है।

चुनौतियों के आगे ढ़ेर नेतृत्व

अमरीका को देखिये, वहां पूर्ण आर्थिक महामन्दी है। अमरीकी अर्थव्यवस्था खुद चल रही है लेकिन वहां की सरकार जनता को आर्थिक मन्दी से उबारने के लिये हरसंभव प्रयास कर रही है। लोगों को एक या दो फीसदी ब्याज दर पर कर्ज मिले रहे हैं। किसी भी तरीके से आर्थिक पहिया घुमाने में अमरीकी प्रशासन दिन–रात लगा हुआ है। एक हमारी अर्थव्यवस्था देखिये जैसे–जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है वैसे–वैसे सरकार अपनी आर्थिक नीति कठोर करती जा रही है।

■ विक्रम उपाध्याय

11 सितम्बर, को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर पर हुए आतंकवादी हमले की दसवीं बरसी पर अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों ने वहां के नागरिकों के लिये एक संदेश जारी किया। उस संदेश में कहा गया कि अमरीका की पुलिस बहुत ही मजबूत और सजग पुलिस है. . . ठीक 4 दिन पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रवेश द्वार के ठीक बाहर एक बम विस्फोट हुआ और भारत के सुरक्षा अधिकारियों ने देश के सामने अपनी मजबूरी जताते हुए कहा कि उन्हें आतंकवादी हमलों के बारे में खुफिया जानकारी होने के बावजूद हमले रोकने में कामयाबी नहीं मिली।

11 सितम्बर, को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर पर हुए आतंकवादी हमले की दसवीं बरसी पर अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों ने वहां के नागरिकों के लिये एक संदेश जारी किया। उस संदेश में कहा गया कि अमरीका की पुलिस बहुत ही मजबूत और सजग पुलिस है। जिसने अपनी सतर्कता के बलबूते अमरीकी नागरिकों को दस साल तक सभी संभावित आतंकवादी हमलों से बचाये रखा। ठीक 4 दिन पहले दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रवेश द्वार के ठीक बाहर एक बम विस्फोट हुआ और भारत के सुरक्षा अधिकारियों ने देश के सामने अपनी मजबूरी जताते हुए कहा कि उन्हें आतंकवादी हमलों के बारे में खुफिया जानकारी होने के बावजूद हमले रोकने में कामयाबी नहीं मिली।

हम उनकी प्रशासन की तरह भारतीय प्रशासन में कभी भी देशवासियों को यह आश्वासन तक नहीं दिया कि उनकी पुलिस व्यवस्था दुरूस्त हो रही है और भविष्य में आतंकवादी हमलों को रोकने में कामयाब भी हो जायेंगे। इसके उलट भारतीय राजनीति में बहुत ऊँचे स्थान पर बिठाये जाने वाले कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी ने हमले के बाद कहा था कि आतंकवादियों को रोका नहीं जा सकता। हमारी स्थिति पाकिस्तान और अफगानिस्तान से तो बेहतर है। इन दोनों की तथ्यों की तरफ पाठकों का ध्यान दिलाने के पीछे मकसद यह नहीं, जनता को यह बताना है कि हमारी कांग्रेस सरकार निकम्मी है और अमरीका में ओबामा की सरकार बहुत सुलझी हुई। इन दोनों तथ्यों की तरफ ध्यान दिलाने का सिर्फ एक मकसद यह जानना है कि क्या हमारा नेतृत्व चुनौतियों से पार पाने में

सक्षम है। इनके कंधे पर देश के नेतृत्व का भार है या जिन कंधों पर देश का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी रखने तमाम कवायदें हो रही हैं। क्या वे कंधे इसके काबिल हैं? सवाल किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि देश के पूरे राजनीतिक नेतृत्व को लेकर है। मामला सिर्फ आतंकवाद या आतंकवादी हमले तक सीमित नहीं, देश की तमाम चुनौतियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या हम सक्षम देश के अक्षम नेतृत्व की स्थिति में नहीं हैं। विश्लेषण एक–दो महीने का नहीं पिछले एक दशक का करें तो हमें लगेगा कि हमें सोफ्ट स्टेट के रूप में परिभाषित किया जा रहा है। हमारी अपनी स्वतंत्र नीति होते हुए भी उनका अनुपालन हम विदेशी इशारों पर कर रहे हैं। चाहे आर्थिक मामला हो या सामरिक या फिर कूटनीतिक। हर जगह लगता है कि पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है पर जनता के सामने कुछ और परोसा जा रहा है।

पहले आर्थिक मामले की चर्चा करते हैं। लगातार पांच साल से देश महंगाई की मार झेल रहा है। आर्थिक विकास की गति 7.5–8 फीसदी तक प्राप्त करने का दावा करने वाली सरकार महंगाई के आंकड़े को कम करने में बुरी तरह फेल हुई है। खाद्य पदार्थों की महंगाई दर 10 फीसदी से ऊपर चल रही है। कभी तेल की मारामारी तो कभी चीनी का टोटा, कभी प्याज को लेकर किल्लत तो कभी अनाज के लिये रोना। सरकार टका सा जवाब देती है, प्रधानमंत्री से लेकर कृषि मंत्री तक एक ही बात कहते हैं कि उनके पास जादू की छड़ी नहीं। भला उन्हें कौन बताये कि सत्ता के पटल पर उन्हें जनता ने जादू के खेल के लिये नहीं भेजा है। बल्कि अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने और आम जीवन सुलभ बनाने के एक इरादे से जनता ने उन्हें चुना है। लेकिन राजनैतिक नेतृत्व की बानगी देखिये, चीनी गोदाम में सड़ गयी लेकिन बाजार में सस्ती नहीं हुई, गेहूं की लाखों बोरियां बरसात में गल गयीं पर जनता भूखी रही। सुप्रीम कोर्ट तक को इस मामले में सरकार को प्रताड़ लगानी पड़ी पर राजनैतिक नेतृत्व को इसे लेकर कभी पछतावा नहीं हुआ। हर बार टका सा जवाब कि महंगाई अभी कम नहीं हो सकती। दूसरी तरफ अमरीका को देखिये, वहां पूर्ण आर्थिक महामन्दी है। अमरीकी अर्थव्यवस्था खुद चल रही है लेकिन वहां की सरकार जनता को आर्थिक मन्दी से उबारने के लिये हरसंभव प्रयास कर रही है। लोगों को एक या दो फीसदी ब्याज दर पर कर्ज मिले रहे हैं। किसी भी तरीके से आर्थिक पहिया घुमाने में अमरीकी प्रशासन दिन–रात लगा हुआ है। एक हमारी अर्थव्यवस्था देखिये जैसे–जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है वैसे–वैसे

मामला सिर्फ आतंकवाद या आतंकवादी हमले तक सीमित नहीं, देश की तमाम चुनौतियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या हम सक्षम देश के अक्षम नेतृत्व की स्थिति में नहीं हैं। विश्लेषण एक–दो महीने का नहीं पिछले एक दशक का करें तो हमें लगेगा कि हमें सोफ्ट स्टेट के रूप में परिभाषित किया जा रहा है। हमारी अपनी स्वतंत्र नीति होते हुए भी उनका अनुपालन हम विदेशी इशारों पर कर रहे हैं। चाहे आर्थिक मामला हो या सामरिक या फिर कूटनीतिक। हर जगह लगता है कि पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है पर जनता के सामने कुछ और परोसा जा रहा है।